Rs. 5/-

ANTAR RASHTRIYA SAHAYOG PARISHAD BULLETIN

Monthly Newsletter of Indian Council for International Co-operation

Vol. 35 No. 7 JULY, 2022 (16 Pages including Cover)

श्री बालेश्वर अग्रवाल जन्मशताब्दी के अवसर पर

17 जुलाई, 1921–13 मई, 2013

स्व. बालेश्वर अग्रवाल जी के 101 वे जन्म दिवस पर सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि

आत्मकथ्य

✍बालेश्वर अग्रवाल
महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद

यह वक्तव्य श्री बालेश्वर अग्रवाल ने गत वर्ष 17 जुलाई, 2011 को नब्बे वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लिखवाया था।

जीवन के नब्बे वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज जब मैं यह सोच रहा हूँ तो ध्यान में राष्ट्रकवि स्व. श्री माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता 'पुष्प की अभिलाषा' की पंक्तियाँ याद आ रही हैं–

चाह नहीं मैं सुरबाला के, गहनों में गूँथा जाऊँ!
चाह नहीं प्रेमी माला में, बिंध प्यारी को ललचाऊँ!!
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक!
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएँ वीर अनेक!!

राष्ट्र के हित में समाज ने जो निर्देश दिया, उसके अनुसार यथाशक्ति कार्य करने की चेष्टा की। इसमें कितनी सफलता मिली समाज ही तय करे।

सन् 1939 में मैंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की। पिताजी की इच्छा थी कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। मेरे बड़े भाई डॉक्टर बन चुके थे और दूसरे भाई माइनिंग इंजीनियर थे। मुझे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चुना गया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल

गया। इंजीनियरिंग मेरी पसंद का विषय नहीं था। प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा में अच्छे अंक मिले। मैं चार वर्ष में इंजीनियर बन गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क हुआ। मैंने उसके अनुरूप जीवन ढालने का प्रयास किया।

इसके लिए मैंने अविवाहित रहकर काम करने का निर्णय लिया। पिताजी ने मुझे सहयोग दिया। आज मैं पुरानी बातों को सोचता हूँ तो लगता है, निर्णय ठीक रहा।

A.R.S.P. Bulletin

A News & Views Monthly
Published Since 1987

Editor
Keshav G. Parande
(M): 98113 92777

Printer
Avon Printers
D-6, Ranjit Nagar Comm. Complex,
New Delhi-110008
(M): 93123 05230
E-mail: a1printers@gmail.com

Publisher
Keshav G. Parande
Pravasi Bhawan
50, Deendayal Upadhyay Marg,
New Delhi-110002
(M): 98113 92777

Contact
Phone (O) : 011 - 2323 4432

E-mail
arspindia@gmail.com

Website
www.arspindia.org

Price
Rs. 5/- per copy
Rs. 500/- for Life

डालमिया नगर (बिहार) में इंजीनियर के पद पर नियुक्त होकर 1945 से 1948 तक तीन वर्ष तक वहाँ कार्य किया और समाज की सेवा की। दिसंबर 1948 में संघ से सत्याग्रह के अवसर पर भूमिगत हो गया और पटना में मेरे लिए नया कार्यक्षेत्र चुना गया। प्रकाशन कार्य से नया संबंध शुरू हुआ। 'प्रवर्तक' साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 'चंद्रगुप्त प्रकाशन लिमिटेड' नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की।

1951 में मेरे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। हिंदुस्थान समाचार समिति के पटना क्षेत्र का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया, जिसका निवर्हन 30 वर्षों तक (1982 तक) करता रहा। पटना में सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद 1955 में मेरा स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया और दिल्ली कार्यालय का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

दस वर्षों के बाद 1965 में हिंदुस्थान समाचार की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। इस अवधि में कार्य–विस्तार तेजी से हुआ। सारे देश में इसका कार्य फैल गया। 1974 में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया गया। हिंदुस्थान समाचार के कर्मचारियों ने सहकारिता के आधार पर एक सोसाइटी का गठन किया, जिसने कानूनी ढंग से हिंदुस्थान समाचार समिति का स्वामित्व भी प्राप्त किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसादजी ने इसकी सराहना की। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयोग था।

1982 में राजनीतिक कारणों से हिंदुस्थान समाचार के कर्मचारियों में आपसी मतभेद पैदा हो गया, जिसके कारण सहकारिता विभाग ने हिंदुस्थान समाचार समिति का कार्य अपने जिम्मे ले लिया। इस स्थिति में मेरे लिए हिंदुस्थान समाचार में काम करना संभव नहीं था।

इसके बाद समाज ने मेरे लिए एक नया कार्यक्षेत्र चुना–वह था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद। भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग विभिन्न देशों में फैले हुए हैं, उनसे संपर्क करना, उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग देना, संगठन के रूप में कार्य करना बहुत ही कठिन काम था। सभी के सहयोग से इस कार्य में भी मुझे सफलता मिली। श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने भी मेरे कार्यों की सराहना की। 30 वर्षों के अथक परिश्रम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को अब दृढ़ आधार मिल गया है।

भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रवासी भवन के लिए एक प्लॉट आवंटित किया। प्रवासी भवन का निर्माण मेरे लिए एक सपना था, जो सभी के सहयोग से पूर्ण हो गया। इस भवन का शिलान्यास भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 दिसंबर, 2003 को किया और इसका उद्घाटन मॉरीशस के राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने 01 दिसंबर, 2009 को किया।

मेरी एक ही आकांक्षा थी–कार्य करते–करते जीवन समाप्त हो जाए। परंतु कुछ महीने से इसमें सफलता नहीं मिल रही है। मुझे प्रवासी भवन में दूसरे के सहारे से जीवनयापन करना पड़ रहा है। फिर भी प्रवासी भवन में रहकर यथाशक्ति काम देखता रहता हूँ। ■

स्वाधीन भारत की भाषाई पत्रकारिता के प्रेरणा-पुरुष

✍ .अच्युतानंद मिश्र

भारतीय भाषाओं की समाचार पत्रकारिता को अंग्रेजी से अनुवाद की निर्भरता घटाने और सुदूर गाँवों तथा उपेक्षित अंचलों के समाचारों को प्रादेशिक और राष्ट्रीय पटल पर महत्त्व देने का पहला ऐतिहासिक प्रयोग जिस बहुभाषिक सहकारी संवाद समिति 'हिंदुस्थान समाचार' ने किया था, उसके संस्थापक तो आदरणीय दादा साहेब आप्टे थे, लेकिन 1950 से आदरणीय बालेश्वर अग्रवालजी के जुडने के बाद न केवल लघु और मध्यम समाचार–पत्रों के लिए बल्कि हिंदी को राजभाषा और अन्य भाषाओं को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने के लिए संघर्ष करनेवालों को नई ऊर्जा व ओजस्विता प्राप्त हुई थी। 1955 में दिल्ली आने और 1956 में 'हिंदुस्थान समाचार' को सहकारी संस्था का रूप देने के बाद से बालेश्वरजी की पहचान हिंदी पत्रकारिता और हिंदी भाषा के निष्पक्ष एवं निर्भीक योद्धापुरुष के रूप में होने लगी थी। स्वाधीन भारत में भाषाई पत्रकारिता को सुदृढ़ता प्रदान करने में बालेश्वरजी के इस अभूतपूर्व योगदान को इस तरह भी समझा जा सकता है कि पी.टी.आई. और यू.एन.आई. जैसी अंग्रेजी समाचार एजेंसियों को भी हिंदी समाचार सेवा शुरू करनी पड़ी। उस दौर में जब भाषाई पत्रकारिता की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और सार्थकता का दायित्व संपादकों के नियंत्रण से निकालकर स्वामियों, संचालकों और प्रकाशकों ने स्वयं अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था, सरकारों और विज्ञापनदाताओं की कृपा से उसे उद्योग में रूपांतरित कर रहे थे। बालेश्वरजी ने 'हिंदुस्थान समाचार' को सहकारी संस्था का स्वरूप दिया था। पत्रकार और पत्रकारों की सेवा–शर्तों के लिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और वेतन आयोग (वेजबोर्ड) बनाए जा रहे थे। बालेश्वरजी ने संवाद समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उसका अंशधारक स्वामी बना दिया था। साप्ताहिक, पाक्षिक या अन्य समाचार–पत्रों को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी देने के लिए शुरू की गई 'युगवाणी' सेवा का योगदान भी रेखांकित किए जाने योग्य है।

श्री बालेश्वरजी का भाषाई पत्रकारिता में एक अत्यंत उल्लेखनीय योगदान यह भी है कि उन्होंने राष्ट्रवादी चिंतनधारा से जुड़े विभिन्न भाषा–भाषी युवाओं की एक पूरी पौध को पल्लवित करते हुए आगे बढ़ाया। आगे चलकर उनमें से अनेक युवा अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, मराठी और अन्य भाषाओं के न केवल यशस्वी पत्रकार, बल्कि संपादक भी बनाए गए। डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा, श्री श्याम खोसला, श्री अरविंद घोष, श्री पीयूष कांति राय, श्री राजनाथ सिंह, श्री श्याम आचार्य, श्री शिवकुमार गोयल, श्री आलोक मेहता, श्री रामबहादुर राय सहित दर्जनों नामों का उल्लेख किया जा सकता है। इन सभी वरिष्ठ पत्रकारों की योग्यता और संकल्प का ही यह प्रतिफल था कि पूँजी और साधन–विहीन इस संवाद समिति के समाचारों और पत्रकारों को पत्रकारिता में ही नहीं, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी विश्वस्त और सम्मान योग्य माना जाता था। यह तथ्य सबको ज्ञात है कि बालेश्वरजी का प्रभाव और प्रभामंडल का विस्तार संपादकों, संचालकों और हर विचारधारा के राजनेताओं तक था। बालेश्वरजी चाहते तो संवाद समिति के विस्तार के लिए पूँजी जुटाई जा सकती थी, लेकिन उन्हें 'हिंदुस्थान समाचार' के स्वरूप में परिवर्तन अथवा समाचारों की निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ कोई समझौता मंजूर नहीं था।

'हिंदुस्थान समाचार' को पूरे देश में पहुँचाने के साथ ही बालेश्वरजी का एक बड़ा योगदान यह भी है कि उन्होंने 'हिंदी टेलीप्रिंटर' के निर्माण और प्रयोग में बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्हें इसके लिए उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री जगजीवन राम, सेठ गोविंददास, डॉक्टर रामसुमग सिंह, बाबू गंगाशरण सिंह, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य भाषाओं के विद्वान राजनेताओं का सहयोग तथा आशीर्वाद प्राप्त था। अपनी निजी जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्यों में सरकारें चाहे कांग्रेस की हों, संविद की या मार्क्सवादियों की, लेकिन बालेश्वरजी का निजी रिश्ता सभी मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के प्रमुख नेताओं से था। मुंबई में एक बार बातचीत में महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले ने मुझे बताया था कि पूरे पत्रकारों में उनकी सबसे अच्छी दोस्ती बालेश्वरजी से है। आपातकाल के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध और 'समाचार' के गठन के बाद की कहानी किसी से छिपी नहीं है। उस दौर में और 1980 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के सत्ता में लौटने के बाद 'हिंदुस्थान समाचार' पर जो संकट आया था और किस तरह पूरी संवाद समिति को निष्प्रभावी किया गया, इसकी कहानी लंबी और दर्दनाक है।

आपातकाल समाप्ङत होने के बाद ही 1978 में 'अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद्' का पंजीकरण कराया गया था और बालेश्वरजी ही उसके प्रेरणास्रोत थे। उनका बेहद निकट और आत्मीय रिश्ता उन देशों के साथ पहले से ही था, जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं। नेपाल, फीजी, मॉरीशस में रहनेवाले भारतवंशियों के साथ तो उनके इतने निकट रिश्ते थे कि उन्हें भारत का अघोषित राजदूत ही कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, सूरीनाम, गुयाना, जमैका के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद् ने भारत के साथ सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। प्रवासी भारतीयों के हर सम्मेलन में बालेश्वरजी की भूमिका देखने योग्य होती थी। गैर–सरकारी स्तर पर कोई एक संस्था कितनी बड़ी सांस्कृतिक भूमिका निभा सकती है, इसका ही प्रत्यक्ष प्रमाण है 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद्'। बालेश्वरजी आत्म–प्रचार से विमुख एक ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष थे, जिनकी प्रत्येक साँस उन महान आदर्शों से प्रेरित थी, जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने तय किए थे। उनके योगदान को समग्रता के साथ अगर देश के युवाओं के सामने रखा जाए तो उन्हें संघर्ष–संकल्प और देशप्रेम की नई ऊर्जा प्राप्त होगी।

सुप्रसिद्ध पत्रकार, पूर्व कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल ■

बालेश्वर जी के अंतरंग में नेपाल भारत संबंध

✍ श्याम परांडे

नेपाल भारत संबंध अनादि काल से चले आ रहे है और वह राष्ट्रीय जीवन के सभी आयामों से जुड़े हुए है। भारत में नेपाल के विषय में हर हमेशा भावनिक एकता रही है और नेपाल में भी इससे कुछ भिन्न नहीं। किन्तु नेपाल में इस बीच कुछ बदल हुए है जिसके कारण भारत में चिंता बढ़ी है। सामान्यतः नेपाली समाज और भारतीय समाज सांस्कृतिक, परम्पराओं से, सामाजिक रूप से ऐतिहासिक समय से पड़ोसी देशों की तरह और एक ही सभ्यता होकर विकसित हुए है। हाल की परिस्थितियां इससे भिन्न है।

नेपाल नरेश महाराज त्रिभुवन बीर बिक्रम के निधन के पश्चात् महाराज महेंद्र बीर बिक्रम ने 1955 में सत्ता संभाली किन्तु उनका विधिवत राज्यभिषेक 2 मई 1956 को हुआ। उन्होंने 15 दिसंबर 1960 संविधान हटाकर पूर्णतःसत्ता स्वय के हाथों में ले ली।

बालेश्वरजी का सम्बन्ध नेपाल से जो विद्यार्थी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पढ़ने के लिये आते थे उनसे उनके विद्यार्थी दशा में ही आया था और उनमे से जो विद्यार्थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ते थे या फिर विद्यार्थी संघटनो में सक्रिय होते थे उनसे बहुत घनिष्ठता से होता था। उन्हीं में एक नेपाली विद्यार्थी थे डॉ. तुलसी गिरी, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने। इन सारे संबंधों के कारण बालेश्वरजी को नेपाल की सामाजिक तथा राजकीय परिस्थिति की समझ उन दिनों से ही बनती गई और वे नेपाल के विषय में गहराई से चिंतन करने लगे और वहां के जो सामाजिक तथा राजकीय बदल होते गए उन पर बारीकी से ध्यान रखने लगे। उन्होंने पटना से एक पाक्षिक करीब तीन दशक चलाया जिसका नाम था "नेपाल सन्देश" तथा जिसके संपादन का कार्य उन्होंने श्री रामाश्रय को सौंपा था।

1960 के दशक में हिन्दुस्थान समाचार की जिम्मेदारी के कारण तथा पटना के केंद्र होने के कारण उनका नेपाल के तराई क्षेत्र में हर माह में जाना होता था और कभी कभार काठमांडू भी जाना होता था। जिसके कारण उनके नेपाल के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजकीय नेतृत्व से घने सम्बन्ध बनते गए। इन संबंधों में नेपाल नरेश महेंद्र बीर बिक्रम देव शाह भी थे जिनसे वे आने वाले समय में मिलते रहे और भारत नेपाल का रिश्ता और भी गहन हो इसका वे प्रयास करते रहते थे। बाद में महाराज बीरेंद्र बीर बिक्रम के साथ उनके सम्बन्ध और भी अच्छे बन गए।

1970 के दशक में वे जब हिन्दुस्थान समाचार के कार्यनिमित्त दिल्ली स्थित हो गए तो भारत सरकार के नेतृत्व से भी पत्रकारिता के कारण उनके सम्बन्ध अच्छे बन गए थे। इन संबंधों के कारण भारत सरकार और विशेष कर विदेश मंत्रालय नेपाल के विषय में उनसे चर्चा करती थी और सलाह भी लेती थी। आने वाले समय में भारत के विविध सरकारों ने उन्हें नेपाल के परिवर्तनों के दौरान काठमांडू भेजा। भारतीय जनसंघ के शीर्षस्थ नेतृत्व से उनके संघ प्रचारक के नाते घनिष्ठ सम्बन्ध थे ही किंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से सम्बन्ध बन गए थे।

इस लम्बे समय के संबंधों के कारण और योजनाबद्ध प्रयासों के कारण बालेश्वर जी का अधिकार नेपाल में भी सभी राजकीय पक्ष तथा नेतृत्व मानता था। वे सभी दिल्ली आकर बालेश्वर जी से सलाह करते थे तथा जब बालेश्वर जी नेपाल जाते थे तो मिलते थे। बालेश्वरजी का नेपाली कांग्रेस पार्टी में वजन था किंतु वामपंथियों से संबंध कम नहीं थे जिसके कारण दोनों देशों का नेतृत्व उनका भारत नेपाल संबंधों में उपयोग करती थी। श्री रविंद्र किशोर सिन्हा, जो लम्बे समय के लिए उनसे जुड़े रहे और हिन्दुस्थान समाचार में भी कार्यरत थे, कहते है की "पार्टी कोई भी हो, भारत के नेपाल स्थित राजदूत कोई भी हो, बालेश्वर जी भारत के नेपाल निमित्त अनौपचारिक राजदूत बने रहे"।

नीतिगत भारत नेपाल संबंधों की बात करें

नेपाल स्थित राजदूत कोई भी हो, बालेश्वर जी भारत के नेपाल निमित्त अनौपचारिक राजदूत बने रहे"।

नीतिगत भारत नेपाल संबंधों की बात करें तो बालेश्वर जी ने तीन सूत्र थे जिसपर वे लगतार कार्य करते रहे– नेपाल में भी और भारत में भी।

प्रथम दोनों देशों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को दृढ करना। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र के सामाजिक नेतृत्व से उनकी घनिष्ठता उतनी ही मजबूत थी जितनी उनकी नेपाल के तराई क्षेत्र के सामजिक नेतृत्व से थी ।

दूसरा है राजकीय स्तर पर संबंध जिसके अंतर्गत वे भारत स्थित सभी विचार प्रवाहों के नेताओं से बातचीत करते, जिसमे भाजपा, कांग्रेस, सोशलिस्ट तथा वामपंथी थे और इन सभी से वे अपनी बात पूर्ण खुलकर करते थे। नेपाल में भी उन्होंने यह नीति अपने और जैसे पहले कहा है की नेपाल में राजावादिओं से लेकर माओवादिओं तक सभी पर उन्होंने अपना प्रभाव संबंधों के आधार पर डाला था।

तीसरा सूत्र था प्रजातंत्र पर आधारित हिन्दू राष्ट्र। इस विषय में दोनों देशों में काफी असमंजस की परिस्थिति थी जो आज भी दिखाई देती है। नेपाल में हिन्दू राष्ट्र को राजावादिओं से जोड़ा जाता है जो ठीक नहीं है। उनकी यह स्पष्टता थी की हिन्दू समाज पारंपरिक रूप से लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता आया है। यह मानना की हिन्दूराष्ट्र में अन्य मतावलम्बिओं पर अन्याय होगा यह सरासर गलत है। नेपाल में आज सेकुलरिज्म के चलते जितना क्रिस्चियन मतांतरण हो रहा है उतना ही राजसत्ता के दौरान भी था। अभी–अभी नेपाल के मुस्लिम समाज से मांग आयी है की सेकुलरिज्म के कारण उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है और उन्हें राजतंत्र की और लौटने से कोई समस्या नहीं है।

Contd. on page no. 14 →

Beacon Light of Indian Diaspora

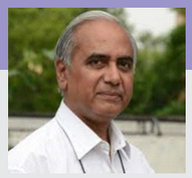

✍ *Seshadari Chari*

The Antar Rashtriya Sahayog Parishad (ARSP) was founded in 1978, but the idea of ARSP, (Indian Council for International Cooperation) was probably as old as the first Indian who set out of the confines of his area to explore the world outside.

For Shri Baleshwarji founding the ARSP was not simply an idea but the beginning of realising a grand dream, a dream to weave a network with all the people of Indian origin in every country of their adoption. When he decided to begin this work, he was, like all great men, alone. However, people started pouring in and soon it became a caravan. His one room office and contacts worldwide was all the capital he had. But he began working undeterred. His dream was fulfilled when the foundation stone of the "Pravasi Bhavan" was laid and slowly the institution was built.

All successful achievers are said to be life-long learners, always looking for new people, skills, insights, and ideas. If they're not learning, they feel thay not growing, not progressing towards excellence. Baleshwarji was one such achiever. When he began working on the idea of Indian Diaspora even the terminologies like NRI were not in currency. The idea of People of Indian Origin (PIO) was probably unheard of. We did not have the much hyped ministry for Overseas Indians, as the PIO is now called. It was the result of tireless efforts of one single individual that this term gained popularity and currency.

Even before the formation of the ARSP, Baleswarji had successfully launched the Hindusthan Samachar (HS), a news agency in Indian languages. As a young RSS activist his organisational and administrative qualities were noticed by senior RSS leaders in Patna where he was working around 1950-51. The idea of a news agency had just being developed. It was five or six years after the launch of English and Hindi weeklies by a group of dedicated swayamsevaks of the RSS. Therefore, a news agency was probably a natural step to follow. The growth and spread of Hindusthan Samachar in Patna, Delhi and Nepal is a story worthy of chronicle as an independent write up or even a book. Realising the economic potential of Mumbai (then Bombay) and the need for more capital infusion, Baleshwarji had deputed Shri Ram Shankar Agnihotri to Mumbai in 1973 to look for helping hands. The HS office was a small temporary office in the upmarket Nariman Point opposite the LIC office (Yogakshema), the present state head office of the BJP. As a young RSS activist I was drafted as one of the assistants for the Hindusthan Samachar. Though we did not do very well in collecting money, all the same we made a mark as a news agency. Soon, political events like the railway strike and the Nav Nirman Movement in Gujarat set in motion series of actions impacting politics. The infamous Emergency in 1975 drew the curtains on the fledgling Hindusthan Samachar in Mumbai. But nonetheless, it was my first and lasting association with journalism, for which I remain indebted to Baleshwarji and Ram Shankar Agnihotri.

During his frequent visits to Mumbai Baleshwarji made it a point to meet a number of persons and enlarge the ARSP group. He proposed the idea of starting a news bulletin of ARSP and put in place a small team to produce the journal. The journal did see the light of the day for a few months but soon had to be wound up for want of continued support. Being a person of strong will power, Baleshwarji could not see his ideas not materialising. The publication of the news bulletin from Delhi must have been the result of this experiment.

When I came to Delhi in 1992 as the Editor of ORGANISER, Baleshwarji personally came to see me in my office and thus renewed my ARSP connection once again. He not only wrote regularly on Nepal and Bhutan for ORGANISER but introduced me to a larger world outside. I travelled with him to Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Mauritius. In all his visits he would introduce me and my paper and insist on full coverage of the political and social situation in these countries as well as the status of the people of Indian Origin there. A tough task master that he was, he would make me file the daily report before dinner, would read it and suggest corrections. (As a result, I was never part of the sightseeing in any of these places, but in retrospect, no regrets. It is a very small price to pay for learning from this noble teacher). In sharp contrast to big ticket meetings, long reports and huge receptions, our visits were on a small shoe-string budget, with every rupee accounted for.

Every living minute of his life Baleshwarji planned for the next step in the history of ARSP. It was difficult to understand his actions but he would gradually reveal his plans and always come up with the perfect team to execute them.

Today, the ARSP has a large presence all over the world and many PIOs turn to ARSP for anything, from finding their roots in a remote village in Bihar to getting to know more about the country of their origin which their forefathers left two-three centuries ago as indentured labourers.

The life and achievements of Shri Baleshwarji is not just a matter of record, but a chronicle of the history of the struggle and success of millions of "pravasi" Indians settled all over the globe, functioning as heads of state, occupying high positions, fuelling the economy of the country of their adoption or shining as bright stars of future.

The ARSP thus, became a platform for the Indian Diaspora, its success story, milestones in their achievements and the challenges they face. Truly speaking the Indian Diaspora is one of the single largest asset we have in our external relations and in our efforts to forge a meaningful and cordial relationship with the outside world. More importantly, every time we look at the issues concerning Indian Diaspora, one can not but think of the pioneer of this movement, Baleshwar Agrawal.

■

Baleshwar Agrawal-In eternal pursuit of National Service

Gopal Arora

"Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail."
Ralph W Emerson

Shri Baleshwar Agrawal was born on 17th July 1921 at Balasore(Orissa). He graduated in Engineering from Banaras Hindu University in 1945 and served as an Engineer for three years in Rohtas Industries Ltd. Dalmia Nagar(Bihar).

His public life began in 1949-first as Managing Director, Chandragupta Prakashan Ltd., which was set up as a Public Ltd. Company for publication of Patriotic literature in Hindi and English. He also brought out a Hindi weekly paper under the title 'Pravartak' for a few years.

It was in early 1951 that he was called upon to take up the challenging task of establishing 'Hindusthan Samachar', a multi lingual National news agency. He began his journalistic career from Patna and established the centre in four years. It was during this period that he came inclose contact with Nepal, a contact he has maintained till now. He moved to Delhi in 1955 as the Bureau Chief. he was instrumental in registering the Hindusthan Samachar Cooperative Society with the help of its workers which ultimately took over the control from the Private Ltd. Co. in 1957. During the next decade, the work of the news agency expanded to almost all the State capitals. He was a pioneer in using Nagari script teleprinters for transmission of news from one centre to another. The agency started distributing its news service to all the important Indian language newspapers and also to 'All India Radio' which became it subscriber. he treated journalism as a mission for national service. Many of the present day established journalists learnt their first lessons of journalism from him. He retired from 'Hindusthan Samachar' 1982.

In 1978, Shri Baleshwar Agrawal, along with some other public spirited intellectuals and activists, founded the 'Antar Rashtriya Sahayog Parishad-Bharat'(ARSP) and thus started a news chapter in the history of Indian Diaspora. ARSP was instrumental in making a bride between Mother India and its 25 million strong Diaspora settled around the globe. In 1983 Shri Agrawal took over as the Secretary General and under his leadership, ARSP emerged as one of the most effective and prestigious organization of Indian Diaspora.

Such has been the scope and importance of Shri Agrawal's work that several Indian origin Heads of State, Prime Ministers and Parliamentarians of countries with significant presence of Indian Diaspora are his admirers and respect him as the father figure of Indian Diaspora organizations.

He has traveled extensively across the Indian Diaspora countries. He led several goodwill delegations to these countries.

He has played a key role in many landmark developments. Under his leadership, the ARSP has, over the years, organized many International and National conferences, Symposiums and programmes to focus on the need for closer interaction with the Indian Diaspora.
ARSP organized Four International Conferences including one of GOPIO. As a result of his persuasion, the Government of India appointed, in August 2000, a High Level Committee on Indian Diaspora under the chairmanship of Dr. L. M. Singhvi. Shri Baleshwar Agrawal was a prominent member of the four member committee. This Committee made far reaching recommendations, many of which were accepted by the Government. A separate Ministry of Overseas Indian Affairs; Organizing of annual Pravasi Bhartiya Divas; issue of Dual Citizenship to PIO's and voting rights to NRI's are some of the landmark decisions by the Government of India, which were based on December 2001 report of the High Level Committee.

Shri Atal Bihari Vajpai, then Prime Minister of India had lauded Baleshwarji's contribution in 2003 in these words- "... the credit for all that happened on 9th January, (Pravasi Bharatiya Divas celebrations), should ho to Shri Baleshwar Agrawal, Secretary General of the A.R.S.P. He was the initiator of co-ordination the people of Indian origin living in different parts of the world. It was a challenging task but he could do it.'

His Passion for journalism continued along with his pursuit for engaging with the Indian Diaspora. Under his

Contd. on page no. 10

बालेश्वर जी के विराट व्यक्तित्व की सादगी

✍डॉ. जवाहर कर्नावट

बालेश्वर जी से मेरा पहला परिचय सन 1999 की मारीशस यात्रा के दौरान हुआ था। महाशिवरात्रि के अवसर पर जा रहे गुडविल प्रतिनिधिमंडल में मैं भी शामिल था। मॉरीशस की इस यात्रा में मुझे यह अहसास हुआ कि बालेश्वर जी का कार्य क्षेत्र कितना व्यापक है और भारतवंशियों में वह कितने लोकप्रिय हैं। मॉरीशस के तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गणमान्य नागरिकों द्वारा बालेश्वर जी के प्रति जो सम्मान व आत्मीयता का भाव हमें देखने को मिला वह निश्चित ही हमें भी गौरवान्वित करने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के माध्यम से संपूर्ण विश्व के भारतवंशियों को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी दिव्य दृष्टि में यह कार्य सर्वत्र भारतीयता को स्थापित करने जैसा था। विश्व भर में फैले भारतीयों को एकजुट कर एक मंच पर लाने का प्रयास आसान नहीं था किंतु बालेश्वर जी ने अपनी अद्भुत संगठन एवं नेतृत्व क्षमता से यह कार्य कर दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव के रूप में बालेश्वर जी ने भारतीय डायस्पोरा को समृद्ध करने के अनगिनत प्रयास किए। डायस्पोरा के देशों के प्रवासी भारतीयों में भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति विशेष सम्मान का भाव जागृत करने के लिए अनेक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का आयोजन परिषद की ओर से बालेश्वर जी ने किया। अपने पूर्वजों के बारे में जानने और समझने के लिए भारत में उनकी जड़ों तक पहुंचाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की विशेष भूमिका बालेश्वर जी के कारण ही संभव हुई। विश्व भर में फैले भारतीयों की संघर्ष गाथा को सामने लाने और उन्हें मंच पर लाने का कार्य गोपियो (GOPIO) के माध्यम से हुआ। बालेश्वर जी के विशेष प्रयत्नों से 28 से 29 नवंबर 1998 को पूरे विश्व में फैले हुए भारतीय मूल के सांसदों का सम्मेलन दिल्ली में संसद भवन एनेक्सी में संपन्न हुआ था। यह देश के लिए अत्यंत गौरव का क्षण था, जब पूरे विश्व के भारतीय मूल के सांसदों ने भारत के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए अपनी समृद्धि में भारत के योगदान की सराहना की थी। यह भारतीय मूल के लोगों को भारत से जोड़ने की सार्थक पहल थी जो बालेश्वर जी के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाई। बालेश्वर जी की इस पहल से भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भी सजग हुआ और प्रवासी भारतीयों के लिए एक स्पष्ट योजना भी तैयार की गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की विशेष भूमिका रही। यद्यपि परिषद किसी भी राजनीतिक विचारधारा से परे विशुद्ध रूप से

मॉरीशस के प्रख्यात हिंदी लेखक स्व अभिमन्यु अनत के निवास पर
उनके साथ श्री बालेश्वर अग्रवाल जी और डॉ जवाहर कर्नावट

भारतीय डायस्पोरा को विस्तार देने एवं उसके साहित्य को विस्तारित करने में अग्रणी रही है। परिषद ने अनेक प्रकाशनों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारतवंशियों की अपने बलबूते पर समृद्धि हासिल करने की गाथा को बखूबी चित्रित किया है। Pioneers of Prosperity पुस्तक में एशिया, अफ्रीका ,यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन देशों में भारतवंशियों के आगमन, उनके संघर्ष और सफलताओं को व्याख्यायित किया गया है। इस पुस्तक में बालेश्वर जी का लेख 'Importance of the PIO' भी प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि इन 25 से अधिक देशों में 70 से अधिक भारतवंशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री पद पर आसीन हैं। इसके अलावा 300 भारतवंशी इन देशों में संसद के सदस्य हैं. इस प्रकार के प्रकाशन भी श्री बालेश्वर जी की सोच और दृष्टि का ही सुफल था.

मुझे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 6 जनवरी 2001 को भारत में पहली बार आयोजित छठे गोपियो (GOPIO) सम्मेलन में हिस्सेदारी का अवसर भी श्री बालेश्वर जी के कारण ही प्राप्त हुआ था। विश्व भर में फैले भारतवंशियों का यह सम्मेलन अद्वितीय रहा। इस सम्मेलन ने हमारी 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को भी चरितार्थ किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संपूर्ण विश्व के भारतवंशियों को भी आव्हान किया कि वे अपने अपने देश में लहरा रही भारतीय पताका को निरंतर गौरवान्वित करते रहे। इस भव्य आयोजन से बालेश्वर जी की वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रवासी भारतीयों के बीच उनकी गहरी पैठ का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

बालेश्वर जी ने एक पत्रकार के रूप में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। हिंदी समाचार एजेंसी हिंदुथातान समाचार को स्थापित करने में बालेश्वर जी का योगदान किसी से छिपा नहीं है। हिंदी में टेलीप्रिंटर से समाचार प्राप्त करने के माध्यम ने उन सैकडों पत्रकारों को राहत प्रदान की जिन्हें मजबूरन समाचारों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता था। यह पत्रकारिता में हिंदी को स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण पहल रही।

बालेश्वर जी से मेरी मुलाकात अनेक बार गोल मार्केट स्थित परिषद के कार्यालय में हुई। सन 1999 में छठे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन लंदन में हो रहा था। इस सम्मेलन में मुझे भी पेपर प्रस्तुत करना था किंतु लंदन की यात्रा की व्यवस्था करना मेरे लिए इतना सहज नहीं था। इस सम्मेलन में बालेश्वर जी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की ओर से भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुझे भी शामिल कर मेरी राह आसान कर दी। इस प्रतिनिधि मंडल ने लंदन के साथ ही कुछ यूरोपीय देशों की यात्रा भी की। गोल मार्केट, दिल्ली के इस कार्यालय में बैठकर ही बालेश्वर जी ने प्रवासी भवन की कल्पना को साकार किया। आज प्रवासी भवन को देखकर यही प्रतीत होता है कि बालेश्वर जी की एक व्यक्ति नहीं अपितु स्वयं में संस्था के पर्याय बन गए थे। ■

Dialogue with Diaspora

Indian Diaspora in Trinidad and Tobago

✍ *Dr Ruchi Verma*
Research Fellow
DRRC-ARSP

Diaspora Research and Resource Centre (DRRC), Antar Rashtriya Sahayog Parishad (ARSP), New Delhi has started a fortnightly virtual programme, 'Dialogue with Diaspora' in which, important members of Indian diaspora from different countries and well-known Indian experts are invited to share their ideas and experiences for deepening their engagement with India and for networking with global PIOs.

As part of this series, tenth session on Indian Diaspora in Trinidad and Tobago was organised on Tuesday, 21 June 2022. Mr Paras Ramoutar, who is a renowned Journalist in Trinidad and Tobago, was the key speaker. The programme was chaired by Shri Shyam Parande, Secretary General and moderated by Prof. Gopal Arora, Secretary, ARSP. Shri Narayan Kumar, Hon. Director, Shri Mukesh Aggarwal, Vice President, Mrs Renu Sharma, Shri Sanjay Ganjoo, executive committee members of ARSP and Dr Ruchi Verma, Research Fellow, DRRC joined in the discussion.

Mr. Ramoutar shared his personal experience as an Indo-Trinidadian. He shed some light on the struggles and discrimination faced by the Indian community in Trinidad. He also mentioned about some prominent members of Indian community in Trinidad like- Former Prime Ministers of Trinidad Shri Basudev Panday and Mrs Kamla Prasad Bissessar, and also about social worker and educationist Shri Satnarayan Maharaj who have done a lot for the betterment of the country as well as for Indian community in Trinidad. He however, stressed on the need of emergence of an effective and strong leadership among the youth of the Indian community.

While referring to the celebration of the entire month of May as 'Indian Heritage Month' in Trinidad & Tobago and also 30th May as the Indian Arrival Day, Mr. Ramoutar mentioned that Indians are celebrating it with full vigor after two long years of inactiveness due to covid. Several Indian classical dance and music performances like Chatni music are being organised at National Council for Indian Culture (NCIC). He also mentioned about the Ram Leela performances and celebration of every Indian festivals with full enthusiasm and spirit by the Indian community. He however suggested that Indian government need to make efforts and start programmes to revive the thoughts and ideas of Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Ravindranath Tagore, Radha Krishnan, etc among the Indo-Trinidadian youth to make them connected with India.

Some important suggestions emerged during the discussion are given below:

- It was suggested that some interactive programmes should be designed with the help of ARSP for promoting and strengthening Indian culture in Trinidad and Tobago. More insights and depth of the Indian traditions should be provided to the Indian community through these programmes.

- Proposal to start online classes in Hindi for people of Trinidad especially among the youth for reviving the Hindi language. Hindi Classes should be started at primary and secondary level by the High Commission of India and Indian Culture Centre in Trinidad & Tobago.

- It was also suggested to sign the MoU's for higher level teaching and research in Hindi with universities and implement the same as soon as possible.

- Suggestion has also been made to establish a School of Indian Classical Dance and Music with the help of Indian embassy in Trinidad and Tobago.

- There is need to mentor younger generations not only in political leadership but also in the field of social, cultural and entrepreneurial leadership.

The participants praised this dialogue with diaspora initiative and suggested to have more

such sessions with PIOs in Caribbean countries to address their needs and expectations.

** The full recording of the event is available at the link given below: https://youtube.com/watch?v=tXH6hD6WNy4&feature=share ■

Genesis of Indian Arrival Day as a national holiday in Trinidad and Tobago

Paras Ramoutar

After 150 years of Indian Arrival, it was only in 1995, that the Government of Trinidad and Tobago opted to announce a day marking the first arrival of over East Indians here, May 30, 1845.

The Patrick Manning Government had announced that May 30, 1995 would be called Arrival Day, which was a one all day. In 1996, when Basdeo Panday came to the political throne he feverishly announced that May 30 will be Indian Arrival Day which was to be etched in our national calendar.

Despite earlier attempts by the Indian Revival and Reform Committee led by Ramdath Jagessar, the Hindu Seva Sangh with Dool Hanoomansingh and others, the Indian Review Committee led by Kamal Persad and Ashram Maharaj, the Sanatan Dharma Maha Sabha , it was former Member of Parliament for Oropouche, Trevor Sudama who moved a motion in Parliament on October 28, 1994 to have Indian. Arrival Day declared a national holiday annually.

And despite stiff opposition within the corridors of Parliament and in public opinion, Sudama successfully moved the motion which was ably seconded by then MP for Caroni Central, Raymond Pallackdharrysingh. Sudama in his presentation made a strong plea which was buttressed by philosophical and sociological data and facts so that he would have left no stone unturned. This he did with great clarity and maturity, and it was passed with contributions from Members of Parliament. One would imagine that the debate was a very emotional issue, and one had to look at the historical antecedents of the whole question of Indian Arrival, as was the case of the Chinese. Syrians, Africans and Europeans coming here, that each group singularly would have called for similar treatment.

Sudama moaned that the Motion to declare Indian Arrival Day a national holiday was on the Order Paper since 1989, but was only afforded the light of the day on October 28, 1994. Notwithstanding the fact the then Prime Minister Dr Eric Williams had announced that both Divali and Eid would be public holidays from 1966, which was an election year. Later, then Prime Minister George Chambers announced in 1982 that Discovery Day, which was celebrated on the first Monday in August, was to be replaced by Emancipation Day August 1. Both Prime Ministers had ignored the presence of the East Indians in Trinidad and Tobago.

It is worth remembering spirited tone of Sudama when he piloted the motion saying that it must be accepted in the , “spirit of light, in that spirit of seeking what is best for the nation, what is best for the people of Trinidad and Tobago, and indeed, of acknowledging the cultural and plural diversity of our society and where are as a nation today”.

“Madam Speaker(Occah Seepaul) we do not want to put the systems of indentureship and African slavery as counterposed; they are different systems; they are different historical experiences. The conditions under which the African slaves were brought in.”

Sudama must be congratulated for his incisive and straight forward presentation, which would serve as a reference point for any dialogue today or in the coming decades about the relevance of a public holiday to mark Indian Arrival Day in Trinidad and Tobago. Just in March 2017, the world community observed the centenary of the abolition of Indian indentureship, and Trinidad and Tobago was the venue for this historical observance as scores of notably former Prime Ministers, Presidents, Government Ministers, legislators, East Indian leaders, professionals among others gathered to discuss the past and the future role of the 33 million Indian diaspora membership in over 100 countries.

A nation is marked as to how it shows respects for it ethnic groups, and this means equal treatment for everyone, and one is reminded to paraphrase Dr Williams' address to the nation on Independence Day August 1962 that there is No Mother India, No Mother Africa, No Mother China, No Mother Lebanon, but the only Mother is Mother Trinidad and Tobago. And that a Mother cannot discriminate among its children. I think that it was in this vein that Sudama so brilliantly proposed that Indian Arrival Day becomes a national holiday.

The East Indians were brought here between the period 1845 to 1917, when in excess of 147,000, most of whom were devout Hindus who brought with the Ramayana, Gita, Mahabharat, the Puranas, Hanuman Chalisa, among several others, principally from Uttar Pradesh and Bihar, to rescue a dying agricultural economy, and their presence brought new hope and aspirations for the planters, and by extension the national economy. They brought with them new cuisine, jewellry , customs, habits, religion, culture, thought and way of life.

Today, the East Indian community has contributed significantly to the national well-being, prosperity as they are leaders in the professions, corporate sector, business, culture, diplomats, Central Bank Governor in the personality of Winston Dookeran, and politics. And the rest is history for we have had two Prime Ministers of East Indian extraction, namely Basdeo Panday and Kamla Persad-Bissessar.

The East Indian labourers ignited friendship between India and Trinidad and Tobago, despite their geographical distance. The East Indian labourers were brought here to contribute to British capitalism, and they worked hard, very hard and struggled with other ethnic groups for this country's priority, and as well for political freedom and independence. Independence was not a one-party or one ethnic group affair, but rather it was a people's consciousness blended with the different ethnic groups and peoples that made it happen. Today friendship between India and Trinidad and Tobago continues to escalate to greater

heights as the clock ticks, and one could decipher that it would continue to escalate in the coming years and decades,and even centuries.

As we observe the 177th anniversary of Indian Arrival Day, 75th anniversary of India's Independence, and our own 60th anniversary of our Independence, all of these factors make it compulsory for our both countries to continue in this trend of friendship, of growth, and support in all the councils of the world's geopolitical and economic groups.

Trinidad and Tobago have benefitted from India's graciousness in terms of ITEC, consultancies in various endeavours of economic, agricultural, cultural co-operation. Aside to these initiatives, religion and culture continue to dominate the calendar of both countries. The Mahatma Gandhi Centre for CulturalCo-operation which was inked when India's Indira Gandhi came here in October 1968, after 50 years, the project admirably enhances our architectural stock.

This is a first for any diplomat, more so, an Indian diplomat. then Indian High Commissioner, Shri Bishwadip Dey, had embarked on a unique foray of cultural diplomacy by visiting descendants of indentured labourers at their homes and presenting hampers. This must be viewed as a micro engagement initiative, and His Excellency must be publicly commended. Usually, diplomats are noted for presenting macro issues.

Dey told the media these elderly citizens have contributed not only to the development of Trinidad and Tobago, but have played an important role in keeping family values alive and passing on cultural and religious practices from one generation to the next. He continued that there are also," strong family ties in the homes visited where witnessed that love and devotion for the elderly."

Dey added that as "senior members of society, the elderly has had an important guiding role for the local communities and form an historical link for Indian nationals of East Indian origin", as India remains in all of us. The High Commission of India shared in the pride of the Indo-Trinidadian community which remains justly proud of these elders who have carved out their lives though initial struggles in their adopted country

With this trend of co-operation at several levels of governance, the foundation has been established for co-operation in future issues which face the world society, which India continues to play a dominant role, and for which Trinidad and Tobago would fully endorse.

Mr. Chairman, it is long overdue, that the Indian diaspora in Trinidad and Tobago, must embark on the new paradigms, new innovations, new thinking, away from the narrative about the abuse, the suffering, the discrimination, the economic, social and political turmoil. Now is the time to revalidate our presence and demonstrate that all is not lost. The history of nations are founded on the precepts of culture, because cultural dispositions make a society, and make a people. All is not lost. This is a nation of immigrants and we must continue to etch our mark with permanence and continue in this trend. A nation is strong as its people.

On this day, I humbly ask the Government of Trinidad and Tobago to include in the secondary school curriculum the teaching of Indian history and African history. This initiative would certainly help to further to knit us all to another level of acceptance and maturity.
I repeat: A nation is strong as its people.

Mr. Chairman: Let us resolve to continue to maintain and respect our national anthem, and the several streams of nationhood. ■

Contd. from page no. 6

guidance, ARSP brought out several publications. 'Mother India Children Abroad' a series focusing on 13 countries with significant Indian Diaspora; 'Pioneers of Prosperity' highlighting the achievements of PIO's; a monthly ARSP bulletin; special publications to draw attention of the world towards situation in Fiji, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Bhutan and other countries are some of the published works of ARSP.
Pravasi Bhavan has been a cherished dram of Shri Baleshwar Agrawal. The land was allotted in 2002 and the foundation stone was laid by Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpai. Pravasi Bhavan was inaugurated by the President of Mauritius Sir Aneeroodh Jagnauth in December 2009.

Shri Baleshwar Agrawal was honoured by Dr. A. P. J. Abdul Kalam, then Presidnet of India in the Rashtrapati Bhawan on 11th October 2002 for his exceptional deveotion and dedication to propagation of Hindi. He donated the entire money he received on the occasion of his Amrit Mahotsav (75th birth anniversary) and crated a trust Antar Rashtriya Sahayog Nyas. The income from the trust is used to confer the annual Bharat Vanshi Gaurav Samman.

Even though, he commands the respect and affection of dignitaries of the highest order around the world, Shri Baleshwar Agrawal leads a very simple life style with bare minimum necessities for himself. he keeps a low profile but maintains very high standards of morality and integrity.

Shri Baleshwar Agrawal has never sought to be in the headlines. He has made history instead. ■

First Arun Jaitley Memorial Lecture
'Growth through Inclusivity, Inclusivity through Growth'

The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, organised the first 'Arun Jaitley Memorial Lecture' in recognition of Shri Arun Jaitley's invaluable contribution to the nation on 8 July 2022.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, Mr. Tharman Shanmugaratnam, Senior Minister, Government of Singapore, Finance Minister Nirmala Sitharaman and other dignitaries participated in the event at New Delhi. The Prime Minister also addressed the gathering during the event.

The Prime Minister said that the topic of lecture "Growth through Inclusivity, Inclusivity through Growth' is the foundation of the government's development policy. "In simple terms, this theme, according to me, is Sabka Saath Sabka Vikas". He further added, India has made tremendous efforts for inclusive growth which is unparallel in the world. He said, nine crore women got free gas connection and 10 crore toilets have been built for the poor. He said, 45 crore Jan Dhan accounts have been opened and three crore pucca houses have been built for the poor people. The Prime Minister said 3.5 crore poor people got free treatment under the Aysuhman Bharat Scheme. He said, these efforts brought the excluded class into the mainstream and ensured growth.

The keynote address at the first AJML was delivered by Mr. Tharman Shanmugaratnam, Senior Minister, Government of Singapore, on "Growth through Inclusivity, Inclusivity through Growth'. Mr Tharman highlighted that the world is facing four challenges: Rising Geo Political tension, stagflation, Climate Change and Pandemic setting back the developing world. He advocated multilateralism as the way forward for the world to grow as interdependence gives more opportunities to maintain a peaceful global order. He further stated that India faces both great challenges and opportunities in the next 25 years. He emphasised large scale provision of basic social amenities to the population and empowerment of women.

The Singapore Senior Minister praised the achievement of India in the digital world stating that the progress of India was unique among all nations. He underlined the potential of demographic dividend stating the urgent need to skill a large number of youth. He pointed out that high growth cannot be sustained without increase in Inclusivity and without growth one cannot have Inclusivity. India must grow by at least 8-10 per cent in the next 25 years, to create jobs. Increasing convergence between low and high income states will boost growth. In this regard, he underscored the value of labour reforms being brought in by the government, reiterating that export focus is critical to growth. He pointed out that India must address the challenge of child growth stunting through improved nourishment and medical support. Learning outcomes also must improve through improved governance in public schools. Higher education must have a higher applied and skill orientation. Co-empowerment across all sectors, genders, religion is the way.

Remembering the contributions of Arun Jaitley, Nirmala Sitharaman said, he was behind the major economic reforms including Goods and Service Taxes and Insolvency and Bankruptcy Code. ■

Days to Remember

in August, 2022

August 01 : Switzerland National day
August 06 : Jamaica : Independence Day
August 08 : 'Quit India' Day
August 09 : Singapore : National Day
August 11 : Purnima Raksha Bandhan
August 12 : International Youth Day
August 15 : India : Independence Day
August 17 : Indonesia : Independence Day
August 19 : Shrikrishna Janmastami
August 19 : Afghanistan : Independence Day
August 20 : Hungary : National Day
August 24 : Ukraine : Independence Day
August 26 : Amavasya
August 31 : Kyrghyzstan : Independence Day
August 31 : Malaysia : National Day
August 31 : Trinidad & Tobago : Independence Day

PM Modi interacts with Indian Diaspora in Germany ahead of G7 Summit

PM Narendra Modi received a warm welcome from the Indian diaspora in Munich, Germany. He also interacted with the children among the members of the Indian diaspora. Prime Minister visited Germany as part of a two-day visit where he has attended the Group of Seven (G7) Summit under the German Presidency on June 26-27.

Notably, this marks the largest gathering of the Indian diaspora post-pandemic. People from across Europe assembled to celebrate Indian culture, Indian values, Indian dances, and Indian spirits of 'Vasudhaiva Kutumbakam'.

During the first day of his visit, PM Modi had bilateral talks with Argentina's President Alberto Fernandez and also met the Minister-President of Bavaria, Germany's largest state by land area. On 27 June PM Modi attended the G7 summit and had bilateral talks with the US, France, UK, Japan and Germany on the sideline of the G7 summit.

G7 Summit

This year G7 summit had taken place under the German Presidency at Germany's Schloss Elmau. It is significant to mention that the G7 grouping includes Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States and the European Union, however, the host country (the one who holds the presidency) can invite other countries in the summit as well. So, apart from India, Germany has also invited Argentina, Indonesia, Senegal and South Africa to strengthen international collaboration on important issues. The agendas of this G7 summit on which the states have discussion were the Ukraine conflict, Global energy crisis, Global food crisis, Security in the Indo-Pacific region, Countering Beijing and Counter-terrorism. ■

UN adopted Resolution on Multilingualism, mentions Hindi for first time

In a significant initiative, the United Nations General Assembly (UNGA) has adopted an India-sponsored resolution on multilingualism that mentions the Hindi language for the first time. The resolution passed on 10 June 2022 encourages the UN to continue disseminating important communications and messages in official as well as in non-official languages, including in Hindi language.

India's Permanent Representative to the United Nations, Ambassador TS Tirumurti said, “This year, for the first time, the resolution has a mention of Hindi language. The resolution also mentions Bangla and Urdu for the first time. We welcome these additions” “India has been partnering with the UN Department of Global Communications (DGC) since 2018 by providing an extra-budgetary contribution to mainstream and consolidate news and multimedia content in the Hindi language,” he said.

As part of these efforts, 'Hindi @ UN' project was launched in 2018 with an objective to enhance the public outreach of the United Nations in the Hindi language, and to spread greater awareness about global issues among millions of Hindi-speaking populations around the world.

“In this context, I would like to recall UNSC resolution 13(1) adopted in its first session on 1 Feb. 1946, which stated that the United Nations cannot achieve its purposes unless the people of the world are fully informed of its aims and activities,” the Indian envoy said. He further stated it is imperative that multilingualism at the United Nations in a true sense is embraced and India will support the UN in achieving this objective.

Multilingualism is an essential factor in harmonious communication among peoples and an enabler of multilateral diplomacy. It ensures effective participation of all in the Organization's work, as well as greater transparency and efficiencies and better outcomes.

According to UN, “Multilingualism is recognized by the General Assembly as a core value of the Organization. As such, all United Nations Secretariat entities are expected to contribute actively and demonstrate their commitment to this joint endeavor. Multilingualism mandates also call for the mainstreaming of multilingualism throughout the Secretariat.” ■

Diplomatic Postings

Shri Ramu Abbagani (IFS: 2001), presently Ambassador of India to the Dominican Republic, has been concurrently accredited as the **next Ambassador of India to the Republic of Haiti with residence in Santo Domingo.**

Shri Vishvas Vidu Sapkal (IFS: 1998) , presently Joint Secretary in Ministry of External Affairs, has been appointed as the **next Ambassador of India to the Republic of Peru.**

Shri Virander Kumar Paul (IFS: 1991), presently High Commissioner of India to Kenya has been appointed as the **next Ambassador of India to the Republic of Türkiye.**

Ms. Ruchira Kamboj (IFS: 1987), presently Ambassador of India to Bhutan, has been appointed as the **next Ambassador/Permanent Representative of India to the United Nations at New York.**

Shri Naveen Srivastava (IFS:1993), presently Additional Secretary in the Ministry, has been appointed as the **next Ambassador of India to Nepal.** ■

विश्वमंच पर हिंदी

✍लक्ष्मीशंकर वाजपेयी

पूरे देश में तथा विश्व भर के अनेक देशों में बसे हिंदी प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी. पूरे सोशल मीडिया पर यह समाचार छा गया था कि संयुक्त राष्ट्र में अब हिंदी की गूंज सुनाई देगी. दरअसल, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने कामकाज के प्रचार प्रसार के लिए छह आधिकारिक भाषाओं के साथ–साथ पुर्तगाली, स्वाहिली, उर्दू, बांग्ला और हिंदी को भी अपना लिया है.

छह आधिकारिक भाषाएँ हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी और अरबी. झूठ सोशल मीडिया का एक स्थायी भाव बन गया है, अति उत्साही लोगों ने पोस्टर या वीडियो बनाकर यह प्रचारित कर दिया कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की सातवीं भाषा बन गई है और इसे भारत की महान् उपलब्धि बता दिया गया. फिर क्या था, सब खुशी में इतने भावविह्वल हो गए कि बिना सच्चाई जाने झूठे संदेश को फ़ॉरवर्ड करने लगे. जिन्होंने सच बताने का प्रयास किया, उन्हें खुशी में बाधक मानकर ट्रोल किया गया. भारत में एक वर्ग ने खुश होने का एक साधन खोज लिया है कि सच्चाई कुछ भी हो, एक झूठ गढ़ो और फैला दो. खैर, बात हिंदी की हो रही थी. निश्चय ही बहुत खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का प्रवेश हुआ. भले ही 'उर्दू' पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा है और 'बांग्ला' बांग्लादेश की, लेकिन 'हिंदी' के साथ इन मूल रूप से भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाना भी खुशी की बात है.

भारत के हिंदी प्रेमियों, हिंदी सेवियों को संयुक्त राष्ट्र में एक कदम रखने के बाद इस बात पर गहन विचार विमर्श करने का तथा गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है कि हिंदी कैसे अपना सही स्थान पाए. सही स्थान निश्चय ही संयुक्त राष्ट्र की सातवीं आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त करना होगा.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. आबादी के लिहाज़ से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है. हिंदी की बात करें तो लिपि की वैज्ञानिकता, व्याकरण, शब्द संख्या आदि के पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र की किस आधिकारिक भाषा से कम श्रेष्ठ है? लेकिन एक कहावत है, 'अपना दाम खोटा तो परखने वाले का क्या दोष ?' जब संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी के संदर्भ में चर्चा हुई थी, एक विदेशी राजनयिक ने कटाक्ष किया था कि 'पहले अपने देश में तो हिंदी ले आइए.' उन राजनयिक की पोस्टिंग कभी भारत में भी हुई थी और वह भारत में हिंदी की स्थिति से परिचित थे. ऐसा ही एक प्रसंग और याद आता है यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था. सभी देशों के प्रतिनिधि माइक पर आते और अपने–अपने देश की भाषा में बोलकर बैठ जाते. जब भारत की बारी आई तो उसने अंग्रेजी में वक्तव्य दिया. सम्मेलन के संचालक ने चुटकी लेते हुए पूछा, आपकी अपनी कोई भाषा नहीं है। ओह ! याद आया आप लोग तो सदियों गुलाम रहे हैं.' कितना कटु तथा लज्जा में डुबोने वाला कटाक्ष था यह, लेकिन उसे यह अवसर भारतीय प्रतिनिधि ने प्रदान किया था. यह बात दशकों पुरानी है, किंतु भारत में हिंदी को लेकर क्या कोई बुनियादी बदलाव आया है? पिछले दिनों संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव शिमला में आयोजित हुआ. वाहनों से उतरकर लगभग आधा किलोमीटर आयोजन स्थल तक जाना था. दोनों तरफ़ दुकानों में अंग्रेजी के बोर्ड थे, तीन प्रतिष्ठित कवि साथ थे. मैंने कहा, 'हिंदी का कोई अक्षर दिख जाये तो आपको बधाई दे दूँ.' पूरे शिमला में किसी होटल, किसी दुकान में हिंदी नहीं खोज पाएँगे. सिवाय सरकारी कार्यालयों के, जबकि हिमाचल प्रदेश की राजभाषा हिंदी है. तर्क दिया जा सकता है कि शिमला पर्यटन स्थल है. दूसरे प्रांतों से लोग आते हैं. किंतु किसी अन्य हिंदी भाषी प्रान्त के किसी भी नगर में यही दृश्य देखने को मिलेगा.

कुछ हिंदी प्रेमी इस बात से खुश हो लेते हैं कि मुंबई में हिंदी में लिखे साइन बोर्ड दिख जाते हैं, जबकि वह गैर हिंदीभाषी है, किंतु वे बोर्ड हिंदी में नहीं, मराठी में होते हैं, जिसकी लिपि देवनागरी ही है. मराठी भाषियों में कम से कम अपनी भाषा के प्रति सम्मान तो है. हिंदी भाषियों के मन में अपनी हिंदी के प्रति सम्मान कब जागेगा? दिल्ली के ऐरोसिटी चले जाइए, मज़ाल है कि हिंदी का एक अक्षर कहीं दिख जाए. किसी भी मॉल में चले जाइए खोज लीजिए हिंदी का एक अक्षर. क्या आपके संज्ञान में हिंदी भाषी प्रांतों के करोड़ों परिवारों में किसी ऐसे परिवार का पता है, जहाँ बच्चों को ज़रा सी समझ आने पर 'तुम्हारी नोज़ कहाँ है', 'तुम्हारी आइज़ कहाँ है' न सिखाया गया हो. अंग्रेज़ी की घिसी–पिटी पोयम न सिखाई गयी हो.

आप यूके के स्कॉटलैंड जाइए. हर साइनबोर्ड पर पहले स्कॉटिश में लिखा मिलेगा, फिर अंग्रेजी में. वेल्स जाइए, तो पहले वहाँ की भाषा में फिर अंग्रेजी के नाम पर मिलेंगे. हिंदी से रोज़ी रोटी कमाने वाला भी अंग्रेज़ी में विज़िटिंग कार्ड थमाएगा. अंग्रेजी से करोड़ों रुपये कमाने वाले अभिनेता–अभिनेत्रियाँ अंग्रेज़ी में बोलकर शान दिखाते हैं. भले ही चेनल हिंदी का हो या कार्यक्रम भी हिंदी में हो. आज भी भारत के हज़ारों कॉन्चेंट स्कूलों में हिंदी में बात करना प्रतिबंधित है. याद करिए मध्यप्रदेश के कस्बे शिवपुरी की कॉन्चेंट स्कूल की घटना, जहाँ एक बच्चे को कक्षा में अपने साथी से हिंदी में बात करते हुए पकड़ा गया और आठ पेज में 'आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी' (मैं हिंदी में नहीं बोलूँगा) की सज़ा सुनाई गई थी. छात्रों को तरह–तरह की अन्य सजा देने की खबरें भी खूब सामने आई हैं. –अपराध– हिंदी में बात कर लेना. जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के, माँ बाप की इकलौती संतान की आत्महत्या को भी याद करना ज़रूरी है, जिसने लिखा कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, जिसके कारण मुझे अपमान का शिकार होना पड़ता है. इसी तरह इंदौर की प्रतिभावान छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसका अंग्रेजी का पर्चा अच्छा नहीं हुआ. बाद में परिणाम आया तो अंक मिले थे 83. अंग्रेजी का इतना भयावह आतंक. भविष्य नष्ट हो जाने की आशंका. ऐसा आपने दुनिया के किसी और देश में देखा– सुना है कि फ्रांस के किसी छात्र ने इसलिए आत्महत्या कर ली है कि उसे जर्मन अच्छी नहीं आती है? आज भी पूरे

→

देश में जितने भी प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम हैं, चाहे चिकित्सा हो, अभियांत्रिकी या कानून या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आर्किटेक्चर या अन्य, सबका माध्यम, अपवादों को छोड़कर अंग्रेजी है. इसीलिए हर तरफ अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। अंग्रेजी ही आज भी महारानी बनी हुई है। हिंदी दुर्दशा, उपेक्षा की शिकार है. हिंदी भाषियों में हिंदी को लेकर गुलामी की मानसिकता से छुटकारा नहीं मिल रहा है. हिंदी भाषी प्रांतों में भी घर–घर दरवाजे के बाहर अंग्रेजी की नामपट्टियाँ मिलेंगी. मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि के निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में ही मिलेंगे. भले ही किसी हिंदी कवि, लेखक, पत्रकार, हिन्दीसेवी का परिवार क्यों न हो? अंग्रेजी इतनी हावी है कि हिंदी के एक वाक्य में अंग्रेजी के तीन चार शब्द अवश्य प्रवेश पा जाएँगे. कुछ लोग 'हिंग्लिश' को भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने को कटिबद्ध हैं. आत्मीय रिश्तों के लिए मेरी मदर, मेरी मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ़ आदि का बोलबाला है.

आप अपने दिल पर हाथ रखकर,एक संप्रभुतासंपन्न राष्ट्र के गौरवशाली नागरिक के रूप में ईमानदारी से सोचकर बताएँ कि क्या देश में हिंदी की इतनी उपेक्षा, अपमान तथा दुर्दशा के भयावह परिदृश्य के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रवेश पर खुशी मनाना कितना खोखला लगता है? यह ठीक है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बोलते हैं तो खुशी मनाई जाती है. रूस के राष्ट्रपति विमान से उतरते ही नेहरू जी से कहते हैं. 'आवारा हूँ.' राजकपूर की फ़िल्म का संदर्भ और सारे अखबारों की सुर्खियों में यही बाकी होता है. ओबामा भारत में एक सभा में अचानक हिंदी में एक वाक्य 'बड़े बड़े शहरों में' बोल देते हैं तो खुशी की लहर दौड़ जाती है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन में 'नमस्ते,कैसे हैं?' बोलते हैं तो खुशी की लहर दौड़ जाती है. लेकिन इस तरह खुशी मनाने के साथ हिंदी सेवियों को बहुत गंभीर होकर हिंदी को अपने ही देश में सुदृढ़ करना होगा. उसे उसका सम्मानजनक स्थान दिलाना होगा. शासन–प्रशासन में, शिक्षा में, न्याय में, कारोबार में हर क्षेत्र में हिंदी को प्रतिष्ठित करना होगा. गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकना होगा. यदि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में भी यह नहीं हुआ तो कब होगा? अनेक निराशाओं के बीच सुखद यह है कि भारत सरकार में हिंदी में कामकाज बढ़ा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक मंचों पर हिंदी में बोलते हैं. दुनिया भर के भारतवंशी एवं प्रवासी भारतीय हिंदी को अपनी पहचान बनाकर समृद्ध करने में लगे हैं. इंटरनेट ने हिंदी के पक्ष में क्रांतिकारी योगदान दिया है. ऐसे में हिंदी सेवियों को संयुक्त राष्ट्र की सातवीं आधिकारिक भाषा बनाने में जुट जाना चाहिए।

■

(प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका में लिखित संपादकीय से साभार)

Contd. From page no. 4

को नेपाली समाज पर थोपा है और "प्रजातंत्र पर आधारित हिन्दू राष्ट्र संकल्पना" से उन्हें दूर किया है। सद्य परिस्थितियों में जो राजतंत्र की मांग नेपाली समाज उठा रहा है वह इस असमंजस के कारण है। नेपाल नरेश को तथा उनके राज व्यवस्था को यूएनओ में जब मान्यता प्राप्त थी, कारण सभी देश जो विविधता में विश्वास रखते थे, उन का कहना था की नेपाल एक यह परंपरागत हिन्दू राष्ट्र है और इस वैविध्य को बचाए रखना चाहिए।

नेपाल की इस लोकतंत्र की यात्रा को ठीक आंकने वाले कुछ गिने चुने भारतीयों में एक व्यक्ति बालेश्वर जी थे। नेपाली समाज का सामूहिक अंतर्मन को सही आकलन कर उस समाज तथा राष्ट्र को अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति के अनुसार आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य था जिसका एक प्रमुख हिस्सा भारत–नेपाल संबंधों की वृद्धि भी था।

उनके इस आकलन के कारण ही नेपाली समाज और वहां का सम्पूर्ण नेतृत्व उनके बातों पर विश्वास करता था और मार्गदर्शन हेतु उन्हें चाहता था।

हिन्दुस्थान समाचार का स्थान भी बालेश्वर जी के कारण नेपाल में प्रतिष्ठा पा गया। नेपाल में प्रकाशित सभी वार्तापत्र–पत्रिकाएं हिन्दुस्थान समाचार से वार्ताएं लेती थी कारण हिन्दुस्थान समाचार का नेपाली भाषा में संस्करण था। इसके अलावा भारत के हर प्रान्त की वार्ता समाचार उन्हें उपलब्ध होता था। वैसे ही नेपाल से सम्बंधित सभी वार्ता, भारत में उपलब्ध होती थी। दोनों समाजों के बीच एक भाव जगाने का कार्य हिन्दुस्थान समाचार के माध्यम से बालेश्वर जी ने किया था।

बालेश्वर जी का अधिकार नेपाली समाज तथा नेपाल का शीर्ष नेतृत्व भी मानता था यह कहना गलत नहीं होगा। उनके कुछ अनुभव जिन कार्यकर्ता या सहकारियों को मिले है वे सभी इस पर सहमत है। जैसे काठमांडू स्थित एक सहकारी जो बालेश्वर जी के साथ वहां के नेतागण से मिलने जाते थे उनका अनुभव है की नेपाल के एक शीर्षस्थ नेता के घर मिलने बुलाया था। जब समय से पहले पहुंचे तो नेता जी उपस्थित नहीं थे। मिलने में देरी कर दिये तो उस नेता को खूब सुनाया बालेश्वर जी ने की तुम प्रधान मंत्री बनना चाहते हो और समय पालन नहीं कर सकते तो कैसे बनोगे प्रधान मंत्री। खैर, वे नेताजी पश्चात् नेपाल के प्रधान मंत्री बन ही गये थे। और भी एक अनुभव उनके स्वभाव की सतर्कता बताता है। एक नेता से मिलना तय हो रहा था तो उस नेता ने कहा की आप अकेले आये हमारे घर। बालेश्वर जी ने कहा की वे अकेले नहीं आयेंगे, साथ में कोई एक सहकारी तो रहेगा ही। उस नेता को बालेश्वर जी से अकेले में मिलने की इच्छा होगी तो उसने आग्रह किया की अकेले ही आये। बालेश्वर जी ने तुरंत जबाब दिया की वे उस नेता के घर नहीं जायेंगे। अंत में नेता को बालेश्वर जी की बात माननी पडी और साथ में अपने सहकारी को लेकर ही बालेश्वर जी वहां पहुँचे।

मेरे विचार में भारत– नेपाल मैत्री में यदि किसी का सबसे अधिक योगदान होगा तो वह थे श्री बालेश्वर अग्रवाल।

अन्तर्राष्टीय सहयोग परिषद के महासचिव

■

Impact of Covid-19 on Romani People: Cultural Context of Europe's Largest Minority

✍ *Md. Zameer Anwar*
Senior Research Associate,
CRSCR

Europe's largest minority, the Roma are one of the most marginalized and poorest communities in Europe and being hard hit by the Corona Virus pandemic because of the miserable health condition, lowest life expectancy, economic deprivation, discrimination and stigmatization. Around 80% of Europe's 15 million Roma live in densely populated neighbourhoods and cramped in overcrowded houses, and many of them do not gain access to running water. This deprives them of the basic preventive measures like physical distancing and sanitation required to combat the permeation of the virus. In some countries this has set up Roma community as a scapegoat for potential virus hotspots.

Many a political measures, taken on account of COVID-19 pandemic, have led to an unprecedented freezing of economic life of the community: in Europe, most of Romani people earn their livelihood by vending in street markets which have been closed. One of the chief sources of income of Roma Community is music, however, the political restrictions have had the consequences of the closure of activities and places such as theaters, restaurants, festival celebration, and ceremonial solemnization and so on where Romani artists used to perform and earn their livelihood. According to report by European Roma Institute for Arts and Culture, it is estimated that 70 percent of Roma who earn a living from the arts and culture industries are not able to cover their basic necessities.

Roma in Spain, Sweden and Eastern European countries are being especially vulnerable to COVID-19 both on health and in socio-economic situation. Discrimination in form of antigypsyism, antiziganism, social segregation especially in housing, economic precariousness and lack of basic services are chronic conditions suffered by Romani families.

Europe failing to protect Roma

Roma community is one of the most vulnerable and affected group of Covid-19 and it has shown the anti-Roma system including administrative structure and failure in the implementation of policies for inclusion of Romani people. The pandemic has uncloaked the deep-rooted and long-standing discrimination against Roma and perpetrating the perpetual stigmatization against them in Europe.

The European Commission and Parliament floundered on protecting the basic rights of Roma community in Europe in the time of Covid-19. The 80 percent of Romani people live in overcrowded houses which run short of drinkable and running water, besides that sewage systems are broken and dilapidated. European Romani Communities experience acute institutional racism and discrimination during the COVID-19 lockdown measures across the blocs. On top of that, Roma were also among the groups the worst affected by the economic and social knock-on effects of the pandemic.

According to report, conducted by the European Roma Rights Center (EERC), there has been routine violation of human rights of Roma Community in 12 European countries – Albania, Belgium, Bulgaria, Hungary, Italy, Moldova, North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Turkey and Ukraine. The disadvantaged Romani people are being brutalised by racist police officers, forcefully evicted from their homes and denied equal access to healthcare; furthermore, Roma children are being denied access to education.

The situation of Romani people in the EU has been deplorable, Members of European Parliament (MEP) made complaints that a significant number of Romani people in Europe live in “extremely precarious” conditions, with most of them deprived of their fundamental rights.

MEPs called on the Commission to table a legislative proposal focused on fighting poverty and anti-gypsyism as well as improving Romani people's living and health conditions. The proposal should include a plan to eliminate inequalities in housing, health, employment and education as well as stipulate specific binding objectives to ameliorate inclusion and assimilation in the mainstream societies. Many of European Governments fizzled on the implementation of specific measures to address the vulnerability of Roma in the time of the Corona virus pandemic. As a result, they are stuck in the multi-dimensional poverty, leading to the pitiable life for Romani people across Europe. ■

POSTED AT LPC, DELHI RMS, DELHI-110 006 on 20-21 of every month
Postal Reg. No. DL(C)–01/1350/2021-23
RNI No 49200/89

Published on 15/07/2022

भारतीय स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष

जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी, 1889 को काशी के गोवर्धनसराय में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवीप्रसाद जी भी दान देने के साथ–साथ कलाकारों का आदर करने के लिये विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशीनरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवीप्रसाद का ही स्वागत करती थी।

जयशंकर प्रसाद
30 जनवरी, 1889--15 नवम्बर, 1937

जयशंकर प्रसाद हिन्दी के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिन्दी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ीबोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुँचकर वह काव्य प्रेरक शक्तिकाव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के, प्रगतिशील एवं नयी कविता दोनों धाराओं के, प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ीबोली हिन्दी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गयी।

आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युगप्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिन्दी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियाँ दीं। कवि के रूप में वे निराला, पन्त, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तम्भ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं; नाटक लेखन में भारतेन्दु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युगप्रवर्तक नाटककार रहे जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती ही गयी है।

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला
स्वतंत्रता पुकारती !

अमर्त्य वीरपुत्र हो, दृढ प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है –बढे चलो, बढे चलो!

असंख्य कीर्ति–रश्मियाँ,
विकीर्ण दिव्य दाह–सी
सपूत मातृभूमि के,
रुको न शूर साहसी !

अराति सैन्य सिंधु में,
सुवाड़वाग्नि–से जलो,
प्रवीर हो जयी बनो – बढे चलो, बढे चलो !